आकाशवाणी शिमला
04.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार''

- प्रदेश सरकार ने समयबद्ध आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा नियमों में दी ढील।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–जी.एस.टी. दरों में कमी से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत।
- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आपदा में नदियों में बड़ी मात्रा में कटी हुई लकड़ी आने पर जताई चिंता–जांच की मांग।

और

- प्रदेश में भारी वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित–कुल्लू भूस्खलन में एक की मौत, 6 अभी भी लापता।

.....

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत सरकार ने समयबद्ध राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्रामसभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नये कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मणिमहेश

इस बीच चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि आज अभियान के तहत 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को हैलीकॉप्टर से चंबा पहुंचाया गया। आज 5 सौ और श्रद्धालुओं को भी सड़क मार्ग से चंबा पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले कई दिनों से भरमौर में ग्राउंड जीरो पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जीएसटी दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि बजार में भी सकारात्मक माहौल

पिछले कल जो फैसला लिया गया जीएसटी काउंसिल में और उस फैसले में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं जो बहुत बड़े सेक्टर भारत के जो अंदर हैं उनको उसका लाभ होगा विशेष तौर से एग्रीकल्चरसेक्टर की अगर मैं बात करूं जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ-साथ में पूरे देश की अगर मैं बात कहूं 80: जो है वह किसान भागवान है ऐसे में बहुत बड़ी राहतएग्रीकल्चर सेक्टर में जो दी गई है जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में तो वो एक बहुतबड़ा ऐतिहासिक कदम हैए एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ-साथ में हेल्थ सेक्टर मेंभी बहुत बड़ा लाभ जो है वो भारत के लोगों को मिला है.

इस बीच जीएसटी में राहत का आम जनता ने भी स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी जिसका सीधा फायदा मध्यमवर्ग के परिवारों को होगा।

जीएसटी 1जीएसटी के लिए जो मोदी सरकार ने किया ये जो मध्यम वर्ग परिवार है उनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया गया है इससे हर चीज में सहूलत मिलेगी आप कुछ भी देख लीजिए जब खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या रोजमरा की जो भी चीजें हैं उसमें तो मैं तो समझता हूं इसे जो हमारे वद वर्ग परिवार है उसके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया गया है एक किसम से मोदी जी ने तोहफा ही दिया है.

–किशोर ठाकुर–

केंद्र सरकार द्वारा यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, इससे हमारे व्यापारी वर्ग, अपने होटलियर्स और अपने हर सेक्टर के जो भी इस सेक्टर में अपने जीएसटी के दायरे में आते थे, उनको बहुत टैक्स से निजात मिलेगी और साथ ही उनका अब व्यापार भी बढ़ेगा और उन्हें नई अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी अपने टैक्स को बचाने की भी.

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के समय अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और झूठ बोल कर जनता को गुमराह कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली पूर्व यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2013 में ही प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए घोषित चार हजार पांच सौ करोड़ रूपए के पैकेज को झूठ करार दिया और कहा कि वास्तव में सरकार ने अभी तक सिर्फ 2 सौ 56 करोड़ रूपए ही इस पैकेज के नाम पर जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार ने स्वयं विधानसभा में लिखित जानकारी दी है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र ही अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला में उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन मशीनों की खरीद प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जाएगी और दिसम्बर तक जनता को इन सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के स्थापित होने से लोगों को निकटवर्ती स्थानों पर ही आधुनिक और विश्वसनीय सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध होंगी।

हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वन विभाग का प्रदेश के जंगलों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपदा के दौरान प्रदेश के जंगलों से आई लकड़ी पर संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा है कि वन अधिकारी जंगलों में जाते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों का नदियों में बह कर आना समझ आता है लेकिन कटी हुई लकड़ी के स्लीपर आना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि प्रदेश के जंगलों में पेड़ कट रहे हैं और वन विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार से इस सारे मामले की जांच की मांग की।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलैक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का सरकार बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। अग्निहोत्री ने आज शिमला में कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रदेश में 46 स्थान चयनित किए गए हैं। इनमें से 34 स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महत्वकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लगभग एक सौ 11 करोड़ रूपए

की ऋण सहायता भी प्राप्त हुई है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल ई–मोबिलिटी क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ रोजगार और अधोसंरचना विकास के नये द्वार भी खोल रही है।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून की वर्षा में आज हल्की कमी आई है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मॉनसून की भारी वर्षा के चलते राज्य में सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच कुल्लू के इन्नर अखाड़ा बाजार में आज सुबह हुए भू–स्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हैं। इस घटना में 6 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू की उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भू–स्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहें। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आज भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त चंबा–भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और मार्ग बहाली के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि खराब मौसम के कारण वायु सेना के दो हैलीकॉप्टर आज चंबा नहीं पहुंच पाये। मौसम खुलते ही ये हैलीकॉप्टर भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने के काम में जुट जाएंगे। भारी वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और एक हजार 2 सौ 8 अन्य सड़कें, एक हजार 8 सौ 85 बिजली ट्रांसफार्मर और 8 सौ 24 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश में अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 6 सितम्बर से वर्षा संबंधित गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।

————————————————————